



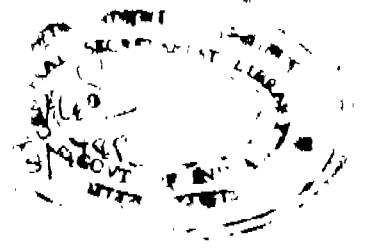
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 263]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1999/ज्येष्ठ 5, 1921

No. 263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 1999/JYAISTHA 5, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1999

सं. 36/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 394 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये 1 जून, 1999 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173छ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ 173छछ. कतिपय विनिर्माताओं द्वारा शुल्क के मासिक संदाय के लिए विशेष प्रक्रिया—(1) प्रत्येक परेषण पर शुल्क के संदाय के संबंध में नियम 173छ में किसी बात के होते हुए भी, किसी वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल पर आधारित अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने वाला कोई विनिर्माता, यथास्थिति, नियम 173छ के अधीन रखा गया चालू खाता या नियम 57छ में विहित प्ररूप आर जी 23क भाग 2 में खाता या नियम 57न में विहित प्ररूप आर जी 23ग भाग 2 में खाता या उक्त सभी खातों से विकलन द्वारा मासिक आधार पर उसके शुल्क दायित्व का उन्मोचन नीचे विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा :

(क) विनिर्माता, यथाशक्य शीघ्र, अग्रिम रूप से लिखित में, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, उस तारीख की जानकारी देगा, जिससे वह इस नियम के अधीन शुल्क के मासिक संदाय की सुविधा प्राप्त करने की आशा करता है;

(ख) विनिर्माता, प्रत्येक परेषण के लिए, हटाए जाने के लिए आशयित उत्पाद-शुल्कय मालों पर शोध्य शुल्क का निर्धारण करेगा और प्ररूप आर जी 1 में ऐसे परेषणों की विशिष्टियां उक्त प्ररूप आर जी 1 में इस उपान्तरण के साथ करेगा कि “शुल्क के संदाय पर” शब्दों के स्थान पर “संदेय शुल्क की रकम” शब्द रखे गए हों;

(ग) विनिर्माता, नियम 52क के अधीन जारी किए गए प्रत्येक बीजक पर संदेय शुल्क की रकम उपदर्शित करेगा;

(घ) विनिर्माता, प्रत्येक कलेंडर मास की समाप्ति पर, कलेंडर मास के दौरान हटाए गए उत्पाद-शुल्कय मालों पर संदेय उत्पाद-शुल्क की कुल

रकम का अवधारण करेगा और वह, यथास्थिति, खालू खाता या प्ररूप आर जी 23क भाग 2 में खाता या प्ररूप आर जी 23ग भाग 2 में या उक्त सभी खातों में विकलन प्रविष्टि करके इस प्रकार संदेय सकल शुल्क दायित्व का उन्मोचन करेगा;

(ङ) किसी कलेंडर मास के लिए शुल्क दायित्व का उन्मोचन उत्तरवर्ती कलेंडर मास के पन्द्रह दिवस के भीतर किया जाएगा।

2. नियम 57क, 57ख और 57ब के प्रयोजनों के लिए उपनियम (1) के अधीन विहित रीति में हटाए गए उत्पाद-शुल्क्य मालों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय किया गया माना जाएगा।

(3) यदि कोई विनिर्माता, किसी कलेंडर मास के लिए संदेश शुल्क की रकम का संदाय उत्तरवर्ती कलेंडर मास के पन्द्रहवें दिन तक करने में असफल रहता है तो वह बकाया रकम के साथ उत्तरवर्ती मास के सोलहवें दिन से आरम्भ होकर बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया रकम पर तीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और पूर्वोक्त अवधि के लिए पांच सौ रुपये प्रति दिन की शास्ति के संदाय का दायी होगा :

परन्तु कलेंडर मास के लिए संदेय शुल्क, ब्याज और शास्ति की कुल रकम उस कलेंडर मास के दौरान निकसियों के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

(4) यदि विनिर्माता, किसी वित्तीय वर्ष में दूसरी बार अनुबद्ध अवधि के भीतर शुल्क दायित्व का उन्मोचन करने में असफल रहता है तो वह सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेश द्वारा जिसमें ऐसी असफलताओं की विशिष्टियों का अभिलेख किया गया हो, किसी वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए इस नियम के अधीन मासिक आधार पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।”।

[फा. सं. 201/10/99-सी एक्स-6]

पी. के. सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना सं. IV डी-सीई, तारीख 28 फरवरी, 1944 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्त्वर्ती संशोधन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/97-के.उ.शु. (एन.टी.) तारीख 1-3-97 और अधिसूचना सं. 35/99-के.उ.शु. (एन.टी.) तारीख 18-5-99 [सा.का.नि. 353(अ) तारीख 18-5-99] द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1999

No. 36/99-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 394 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Eleventh Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on 1st June 1999.

2. In the Central Excise Rules, 1944, after rule 173G, the following rule shall be inserted, namely :—

“173GG.—Special procedure for monthly payment of duty by certain manufacturers. (1) Notwithstanding anything contained in rule 173G in regard to payment of duty on each consignment, a manufacturer availing of the exemption under a notification based on value of clearances in a financial year may discharge his duty liability on a monthly basis by debiting the account-current maintained under rule 173G or account in Form RG 23A Part-II prescribed in rule 57G or account in Form RG 23C Part-II prescribed in rule 57T or all the said accounts, as the case may be, in the manner specified below :

(a) the manufacturer shall inform the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, in writing, in advance, as soon as may be, the date from which he wishes to avail of the facility of monthly payment of duty under this rule;

(b) the manufacturer shall assess the duty due on the excisable goods intended to be removed, for each consignment, and shall enter the particulars of such consignments in Form RG-J with the modification in the said Form RG-J that for the words “On payment of duty”, the words “Amount of duty payable” had been substituted;

- (c) the manufacturer shall indicate on each invoice, issued under rule 52A, the amount of duty payable;
- (d) at the end of each calendar month, the manufacturer shall determine the total amount of excise duty payable on the excisable goods removed during the calendar month, and he shall discharge the total duty liability so payable by making debit entry in the account current or account in Form RG 23A Part-II or Form RG 23C Part-II or all the said accounts, as the case may be;
- (e) the duty liability for a calendar month shall be discharged within fifteen days of the succeeding calendar month.

(2) The duty of excise shall be deemed to have been paid on excisable goods removed in the manner prescribed under sub-rule (1) for the purposes of rules 57A, 57B and 57Q.

(3) If the manufacturer fails to pay the amount of duty payable for a calendar month by the fifteenth of the succeeding calendar month, he shall be liable to pay the outstanding amount along with interest at the rate of thirty per cent per annum on the outstanding amount, for the period starting with the 16th day of the succeeding month till the date of actual payment of the outstanding amount, together with a penalty of five hundred rupees per day for the aforesaid period :

Provided the total amount of duty payable for the calendar month, interest and penalty shall not exceed the value of clearances during that calendar month.

(4) If the manufacturer fails to discharge the duty liability within the stipulated period for the second time in a financial year, he shall not be allowed to pay excise duty on monthly basis under this rule for the remaining part of the financial year, by an order to be passed by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise recording therein the particulars of such failures.”.

[F.No. 201/10/99-CX.6]

P. K. SINHA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. IV D-CE, dated the 28th February, 1944 and subsequently amended by Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 6/97-CE (N.T.) dated 1.3.97 and notification No. 35/99-CE(N.T.) dated 18.5.99 vide G.S.R. No. 353(E) dated 18.5.99.

